



बिहार विधान परिषद्

207वां सत्र

तारांकित प्रश्न

25 जुलाई 2024

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 43

पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में ।

*86 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई) में कार्यरत अनुदेशकों एवं ग्रुप अनुदेशकों के पदनाम क्रमशः प्रशिक्षण अधिकारी एवं वरीय प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि कतिपय राज्यों में उक्त पदनाम परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं है;

(ग) यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों तथा ग्रुप अनुदेशकों का पदनाम परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

लाल बत्ती एवं हूटर लगाने पर प्रतिबंध

*87 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह सही है देश / राज्य में V.I.P. संस्कृति को समाप्त कर दिया गया है तथा किसी भी जनप्रतिनिधि को लाल बत्ती एवं हूटर लगाने पर प्रतिबंध है;
2. क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों को तो लालबत्ती लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परन्तु प्रशासन के कई अधिकारी लगातार बत्ती एवं हूटर का प्रयोग करते हैं, जिस कारण यह नियम देश में V.I.P. संस्कृति को पूर्णतः समाप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शीघ्र अधिकारियों पर भी बत्ती एवं हूटर लगाने पर प्रतिबंध का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्रावास के संबंध में ।

*88 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि रोहतास जिला में अटल बिहारी वाजपेयी छात्रावास की अति आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है, कि अटल बिहारी वाजपेयी छात्रावास निर्माण करना चाहती है;

(ग) क्या यह सही है, कि इस छात्रावास का निर्माण हो जाने से पहाड़ी क्षेत्र एवं दूर दराज से आए हुए बच्चे को शिक्षा लेने में सुविधा मिलेगा।

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी छात्रावास निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई संकट के संबंध में।

*89 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिला, मोतिहारी में 255 राजकीय नलकूप बंद हैं जिससे सिंचाई पर संकट पैदा हो गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिले के किसान निजी बोरिंग से सिंचाई को विवश हैं, क्योंकि 612 में से मात्र 357 नलकूप ही चालू हैं?

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चंपारण जिले के किसानों के हित में सभी नलकूपों को चालू करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

जनहित में पुल निर्माण

*90 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत बसंतपुर पंचायत के बैजनाथपुर वार्ड नं.- 5 शैखटोला में फुलकाहा बेतरनी 6RD नहर के दोनों ओर बड़ी आबादी निवास करती है;

(ख) क्या यह सही है कि बसंतपुर पंचायत के वार्ड नं.- 5 शेख टोला में फुलवाहा बेतरनी 6 RD नहर पर हरेक वर्ष चचरी पुल के निर्माण द्वारा आमजन आवागमन को विवश है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के शेख टोला फुलकाहा बेतरनी 6RD नहर पर जनहित में पुल निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

फलदार वृक्षारोपण कानून

*91 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष वनों की कमी के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से तापमान बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार पर्यावरण की दृष्टि से, जिनके पास एक एकड़ जमीन है, उन्हें भी कम से कम 1 कट्टा खेत में अनिवार्य रूप से फलदार वृक्ष लगाने का कोई कानून बनाना चाहती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसा या इसके समकक्ष कोई कानून बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बाढ़ निरोधक कार्य

*92 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत नौबतपुर प्रखंड के ग्राम पितवांस में पुनपुन नदी पर बने पुल से दक्षिण तट पर मंदिर बना हुआ है जो बाढ़ के कारण कटाव की स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कटाव से बचाव हेतु मंदिर के पास सीढ़ी घाट का निर्माण अथवा बाढ़ निरोधक कार्य करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मंदिर को बचाने हेतु बाढ़ निरोधक कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

यातायात नियमों का पालन

*93 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर, दानापुर, खगौल एवं आस-पास के क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो रिक्शा/टेम्पू में प्रेशर हॉर्न, अश्लील गाना तथा यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं, स्कूल जाने वाली छात्राओं, बच्चों तथा आमजनों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) क्या यह सही है कि ई-रिक्शा बड़ी संख्या में पटना मुख्यालय की सभी सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के यातायात नियम का पालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे आमजन को आवागमन में कठिनाई के साथ-साथ लूट और छिनतई की घटनायें प्रायः होती रहती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऑटो रिक्शा/टेम्पू में अवैध रूप से लगाये गये प्रेशर हॉर्न, लाउडस्पीकर तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए ठोस कार्रवाई करना चाहती है ?

पक्का बांध का निर्माण

*94 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण के बगहा अनुमंडल में बगहा नगर परिषद् के रत्नमाला मौजे के वार्ड संख्या 31,32,33,34 एवं 35 में किसानों की जमीन पर 2015 ई. में तीन-चार फेज में पक्का बांध का निर्माण किया गया परन्तु आज तक किसानों को भूमि के बदले मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि यह बासगीत भूमि है और बाढ़ के दुष्प्रभाव से आबादी को बचाने हेतु विभाग द्वारा उक्त निर्माण कराया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि इस हेतु अवर निबंधन पदाधिकारी, बगहा द्वारा भूमि की किस्म के अनुरूप न्यूनतम मूल्य निर्धारण (एम.वी.आर.) उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है;

(घ) क्या यह सही है कि मुआवजा भुगतान हेतु अधिकारियों द्वारा भांति-भांति के बहाने बनाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार किसानों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान कराना चाहती है और विलंब हेतु दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

आर0सी0सी0 बॉक्स बनाने के संबंध में।

*95 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत फुलवारी प्रखंड के इस्लामपुर, ढिबरा आहर पर्इन योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 द्वारा क्रियान्वयन की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि इस्माइलपुर ग्राम के पास घनी आबादी के कारण ग्रामीणों द्वारा कचरा फेंकने से पर्इन भर गयी है, जिससे जलप्रवाह अवरुद्ध हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य आहर पर्इन जो घनी आबादी से गुजरता है, ग्रामीणों द्वारा कचरा फेंके जाने के कारण जल अवरुद्ध होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घनी आबादी वाले जगहों पर आर0सी0सी0 बॉक्स नाला बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*96 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत नीमाचक बथानी प्रखंड के ग्राम चौसंडी में

कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी को इसी वर्ष पूर्ण करने का विचार रखती हैं ,यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कंक्रीट पुलिया का निर्माण

*97 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के अमीरपुर हरदास (संथाली टोला) में 121 आर.डी. वितरणी पर आवागमन हेतु बांस-चचरी पुल का उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि यह गांव अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल गांव है जहां समाज के गरीब एवं पिछड़े लोग रहते हैं जिनकी आजीविका कृषि पर आधारित है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव की महिला एवं पुरुषों को अपने खेत एवं बाजार जाने में तथा बच्चों को स्कूल आदि जाने में बांस-चचरी पुल का उपयोग करना बाध्यकारी है जो हमेशा खतरनाक बना रहता है;

(घ) क्या यह सही है कि इस वितरणी पर गांव के आगे 600 मीटर पर अवस्थित फाटक का बहाना लेकर यहां कंक्रीट पुलिया बनाने में संकोच किया जाता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विशेष परिस्थिति में इस गांव के वितरणी पर कंक्रीट पुलिया का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

उप कारागार भवन का निर्माण

*98 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल भवन परिसर में व्यवहार न्यायालय, बखरी का संचालन हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरकार ने यह घोषणा की थी कि व्यवहार न्यायालय संबंधी वादों के संचालन में सहूलियत के लिए अनुमंडल में ही कैदी हाजत एवं उप-कारागार भवन का निर्माण किया जाएगा;

(ग) क्या यह सही है कि बखरी अनुमंडल मुख्यालय में 08/05/2015 को स्थापित व्यवहार

न्यायालय, बखरी का अपना कैदी हाजत और उप-कारागार भवन का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों, अधिवक्ताओं एवं स्थानीय पुलिसकर्मियों को बखरी अनुमंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय बेगूसराय के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में ही कैदी हाजत और उप-कारागार भवन का निर्माण शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

गंगा जल आपूर्ति

*99 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत वनगंगा से गुजरकर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत पाईप लाईन के माध्यम से गंगा जल गया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि नारदीगंज प्रखंड के वनगंगा से सटे गाँव सुंदरवन, विजयनगर, सीतारामपुर, जनकपुर, राजीवनगर, जो पहाड़ के निकट स्थित है, यदि इन सभी गाँवों में गंगा जल आपूर्ति का कनेक्शन दे दिया जाय तो ग्रामीणों को जल के संकट से निजात मिल जायेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों के हित में उक्त गाँवों में गंगा जल आपूर्ति का कनेक्शन कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चवर और नदी की साफ़-सफाई

*100 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत प्रखण्ड तरैया के अंधरबाड़ी - डुमरी - शीतलपट्टी के चवर, गंडक नदी और रामकोला तरैया की खादरा नदी में विगत 4 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चवर और नदी की साफ-सफाई विगत 20 वर्षों से नहीं हुई है, जिसके कारण नदी में झाड़ी और जंगल उपज गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ससमय पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों की फसल पैदावार में काफी कमी आई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चवर और नदी की साफ़-सफाई के साथ-साथ ससमय पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं, यदि हां

तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जाँच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने

*101 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा, बगहा 2, मधुबनी, भितहां, पिपरासी, रामनगर प्रखण्डों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सीडीपीओ द्वारा उगाही कराते हुए विवरण में अनियमितता की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखण्डों में अनियमितता की जाँच सचिवालय द्वारा टीम गठित कर कराई गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जाँच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गुडबोले जलाशय योजना

*102 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बाँका जिला के शंभुगंज प्रखण्ड अंतर्गत गुडबोले जलाशय योजना की स्थिति काफी खराब है;

(ख) क्या यह सही है कि शंभुगंज प्रखण्ड के 09 (नौ) पंचायत की खेती गुडबोले जलाशय योजना संचालित नहीं रहने के कारण प्रभावित हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा गुडबोले जलाशय योजना का जीर्णोद्धार शीघ्र कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाम परिवर्तन

*103 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 27-09-2022 को श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत विभागीय स्टेट स्टीयरिंग कमिटी की बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों को कैरियर में आगे बढ़ने हेतु कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी को अनुमोदित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में झारखंड राज्य सहित अन्य राज्यों के अनुरूप

अनुदेशक संवर्ग का पदनाम (Nomenclature) प्रशिक्षण अधिकारी (TO) एवं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी (CTO) के रूप में बदले जाने संबंधी निर्णय को अधिसूचित किए जाने पर सहमति बनी थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त निर्णय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत अनुदेशक संवर्ग का नाम (Nomenclature) परिवर्तित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय वृद्धि पर विचार

***104 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं का मानदेय वृद्धि वर्ष 2019 में की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं का मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन के आदेश दिनांक-22.02.2024 , पत्रांक-03/क्यू-08/2022,संप्र०- 3033 एवं दिनांक 06.11.2023, पत्रांक-03/एम-2023, संप्र०-20615 और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003, दिनांक-22.01.2021 के पेज सं०-04 के पाराग्राफ सं०-03 के "ख" में निदेश किया गया है कि संविदा पर कार्यरत कर्मों का मानदेय प्रत्येक वर्ष पुनरिक्षित किया जा सकेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं के मानदेय वृद्धि का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

वाहनों को अन्यत्र रखने की व्यवस्था

***105 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी पुलिस थानों एवं ओ०पी० पर जब्त गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, जिससे रास्तों पर अतिक्रमण रहता है और आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला के पुनपुन, धनरूआ के साथ गया जिला के आमस थाना में जब्त गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के थानों में जब्त की गई गाड़ियों को अन्यत्र रखने की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ

*106 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मृदुला कुमारी, सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो पटना जिला के बिहटा प्रखंड से दिनांक- 31.01.2020 को सेवानिवृत्त हुई हैं, परंतु चार वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ अबतक नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती कुमारी को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ अबतक नहीं मिलने के कारण पेंशन में इन्हें घोर आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ-ही-साथ एक वर्ष पहले ही इनका किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, जिसके कारण इन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मृदुला कुमारी को तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ शीघ्र प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक

*107 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत थाना-नगरनौसा, काण्ड सं.-37/24 दिनांक 23.02.2024 को श्री पुरुषोत्तम कुमार, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, दिरिपर की हत्या प्रमोद कुमार एवं सुबोध कुमार, पिता-श्री शिवशंकर प्रसाद यादव के द्वारा करा दी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जबकि मृतक की पत्नी के द्वारा इन्हें नामजद बनाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि इस हत्याकाण्ड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु शिकायत पुलिस महानिदेशक, पटना, एस.पी. नालन्दा एवं डी.एस.पी. हिलसा से की गयी है;

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस अनुसंधान में डी.एस.पी. हिलसा की भूमिका

संदेहास्पद है, नामजद अभियुक्तों को मात्र संदेहास्पद रखा गया है, इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी मोटी रकम लेकर नहीं की जा रही है एवं मामले की लीपा-पोती की जा रही है;

(ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच एस.टी.एफ. गठन कराकर हत्या करने एवं करवाने वाले अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***108 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

दिनांक- 19.06.2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक ‘नौकरी के नाम पर हैवानियत; चिटफंड कंपनी में लड़कियों का यौन शोषण’ (प्रेस कतरन की छायाप्रति संलग्न) को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर डीबीआर चिटफंड कंपनी द्वारा लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड (क) में वर्णित शिकायत की न्यायिक जांच हेतु दिनांक- 24.06.2024 को महिलाओं, छात्र, युवाओं एवं अन्य संगठनों द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क, पटना के पास प्रदर्शन किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित शिकायत की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बैंक शाखा स्थापित कब तक

***109 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड (बाजार) में मात्र एक ही पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थित है, जिसके कारण आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत मधवापुर प्रखंड (बाजार) जो भारत नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल एवं व्यवसायियों को भी बैंक शाखा नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आम जनमानस और अन्य वित्तीय कार्यों से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखण्ड में बैंक शाखा को स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

एटीएम की सुविधा

***110 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में एटीएम की कुल संख्या 7155 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1195 एटीएम है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को पर्याप्त संख्या में एटीएम की सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में एटीएम की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ,नहीं तो क्यों ?

स्क्रेप करने की बाध्यता

***111 श्री ललन कुमार सराफ (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वाहन स्क्रेपिंग नीति के तहत 15 साल पुराने (ELV) सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी व निजी वाहनों का स्क्रेपिंग किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि 15 साल पुराने (ELV) वाहनों को पुनः 5 साल के लिये पंजीकरण हेतु सरकार द्वारा अधिकृत आटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ATS) से फिटनेस प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान नियम के अनुसार वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिये जिला परिवहन कार्यालय में केवल इंजन एवं चैसिस नंबर का प्लेट समर्पण करने की बाध्यता है जबकि ऐसे ELV वाहन के लिये अधिकृत वाहन स्क्रेपिंग सेंटर से स्क्रेप कराने की बाध्यता नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि अवैधानिक अनेक स्क्रेपिंग केन्द्र असंगठित रूप से अस्तित्व में हैं, जिनके द्वारा वाहनों की अवैधानिक रूप से स्क्रेपिंग हो रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 15 साल बाद अन्य 5 साल के लिये पंजीकरण हेतु ATS से फिटनेस प्रमाण पत्र की बाध्यता एवं वाहन की स्क्रेपिंग अधिकृत वाहन स्क्रेपिंग सेंटर से स्क्रेप करने की बाध्यता लागू करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कब तक

***112 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत- कुरमुरी, थाना- सिकरहटा, प्रखंड- तरारी, जिला- भोजपुर स्थित सरकारी करहा अनावार सर्व साधारण में अधिसूचित है जिसका मौजा- कुरमुरी, थाना- 199, खाता- 947, खेसरा- 4941, रकबा- 0.15 डिसमिल है ;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय मुखिया द्वारा उक्त सरकारी करहा में बिना लघु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर मिट्टी भरवाकर रास्ता का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है ;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित करहा द्वारा सैकड़ों बीघा खेत की सिंचाई होती है, इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन प्रमंडल, आरा ने भी अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), भोजपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार को अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि पूर्व में ग्रामीणों द्वारा आस-पास के खेतों का पटवन किया जाता था ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार किसानों व सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रख कर उक्त सरकारी करहा को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खेतों की सिंचाई हेतु पुनः उपयुक्त बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

आवासीय भत्ता के संबंध में

***113 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में कई नगर निकायों का उत्क्रमण किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को उत्क्रमित कर नये नगर निकाय भी सृजित किये गये

है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्यकर्मियों को मिलने वाले आवासीय भत्ता वर्गीकृत शहरों अथवा अवर्गीकृत शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों की संशोधित सूची के आलोक में ही प्रावधानित

है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'क' के आलोक में Y एवं Z श्रेणी के शहरी समुह में अन्य सक्षम अथवा मानक पूरा करने वाले शहरों को भी नये सिरे से शामिल करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पुराने पेड़ों की कटाई रोकने के संबंध में

***114 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि बिहार के विकास के लिए सभी जिलों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के क्रम में हजारों पुराने पेड़ों की कटाई से शहर के पर्यावरण संतुलन को क्षति पहुंची है;

(ख) क्या यह सही है, कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं नई सड़कों का निर्माण बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, साथ ही सड़क के किनारे पेड़ों का लगाना भी उतना ही आवश्यक है जितना विकास के लिए सड़क।

(ग) क्या यह सही है, कि पर्यावरण संतुलन में हुई इस क्षति की भरपाई हेतु अबतक सड़क किनारे तथा नहर एवं शहर के मध्य नये पेड़-पौधे नहीं लगाये गए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यावरण संतुलन के लिए क्या प्रयास कर रही है और सभी जिलों में कबतक पेड़ लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बेरोजगारों को रोजगार कब तक

***115 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात लाख से अधिक बेरोजगारों ने रोजी-रोजगार के लिए निबंधन कराया है;

(ख) क्या यह सही है कि 18; वर्ष तक आयु वर्ग के सबसे अधिक बेरोजगार बिहार में हैं जिसके कारण राज्य से बाहर जाकर उन्हें काम करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने राज्य की बेरोजगारी दूर करने के लिए अबतक क्या-क्या उपाय किया हैं और इससे कितने बेरोजगारों को राज्य में अबतक रोजगार मिला है, यदि नहीं तो क्यों?

पुल निर्माण के संबंध में।

***116 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही कि सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के बलुआ बाजार पंचायत के वार्ड संख्या – 14 में गेड़ा नदी अपनी धारा बदलकर सघन बस्ती के समीप से बह रही है;

(ख) क्या यह सही है कि आवागमन के लिए गेड़ा नदी पर एक पुल की आवश्यकता भी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छातापुर प्रखंड के बलुआ बाजार पंचायत के वार्ड नं.- 14 के समीप से बहने वाली गेड़ा नदी को चिरान द्वारा अपने मूल धारा ले जाने एवं आवागमन के लिए एक पुल बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों

जाम से निजात

***117 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना मुख्यालय स्थित दानापुर स्थित बी.एस.कॉलेज से दानापुर बस पड़ाव तक महीनों भयानक जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि बस पड़ाव दानापुर से थाना मोड़ तक नो इंट्री में भी ट्रैक्टर एवं ट्रक की इंट्री कराकर जाम लगा दिया जाता है तथा ई-रिक्शा, टेम्पु भी खुलेआम बिना यातायात नियम के सड़क के किनारे अतिक्रमण कर जाम लगाये रहते हैं जिसकी खबर भी समाचार पत्रों में आती रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बी.एस.कॉलेज से दानापुर बस पड़ाव तक सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाते हुए जाम से निजात दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आहर पर्ईन का जीर्णोद्धार

***118 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी शरीफ प्रखंड में नत्थुपुर आहर पर्ईन का जीर्णोद्धार जिसकी एन0आई0टी0 संख्या 14/2021-22 है, किया जाना था;

- (ख) क्या यह सही है कि नत्थुपुर आहर पर्ईन भरा हुआ है;
- (ग) क्या यह सही है कि नत्थुपुर आहर योजना के बदले निरपुरा आहर पर्ईन योजना का जीर्णोद्धार कर दिया गया है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच करवाकर एजेंसी या संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***119 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अंतर्गत बेलागंज प्रखंड के ग्राम समसपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आच्छादित करने पर विचार

***120 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु तीन या चार पहिया वाहन खरीद पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार देने हेतु नगर निकायों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना के तहत नगर निकाय में शहरी क्षेत्र को आच्छादित करना चाहती है ?

जाँच कराने पर विचार

***121 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत रामनगर प्रखण्ड के ग्राम

मधुबनी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास उत्क्रमण का कार्य कराया जा रहा है ;
(ख) क्या यह सही है, कि उक्त छात्रावास में सरिया, कॉलम की लैपिंग एवं ब्रिक वर्क में सीमेंट 1:०:6 के अनुपात में कार्य नहीं किया जा रहा है;
(ख) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभाग द्वारा जांच टीम गठन कर जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ,नहीं तो क्यों ?

थाना का भवन निर्माण

***122 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला अंतर्गत बुन्देलखण्ड थाना, साईवर थाना, यातायात थाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सही है कि इन सभी थानों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को रहने का भवन नहीं है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को रहने के लिए बुन्देलखण्ड थाना, साईवर थाना, यातायात थाना का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परिपक्वता राशि का भुगतान

***123 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी स्थित बी.एन.आर. काम्प्लेक्स, प्रथम तल्ला गुलजारबाग, पटना साहिब, स्थित सहारा इंडिया नन बैंकिंग कम्पनी स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती महापति देवी ने ई-साइन सर्टिफिकेट नं.- 351001112761, रसीद नं.- 80065245318 राशि (पांच हजार रुपये) एवं रसीद सं.-80065245318, सर्टिफिकेट सं.- 35100112762 राशि (छः हजार रुपये) का निवेश नन बैंकिंग कम्पनी में किया, जिसकी परिपक्वता अवधि दिनांक- 13.08.2019 को ही पूरी हो चुकी है, बार-बार कार्यालय जाने के उपरांत फंड नहीं प्राप्त होने के कारण कम्पनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे श्रीमती देवी के अलावा अन्य निवेशकों में भी आक्रोश व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्रीमती महापति देवी को सहारा इंडिया नन बैंकिंग कम्पनी में निवेश के उपरांत परिपक्वता राशि का भुगतान ब्याज सहित करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय में बढ़ोतरी

*124 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दशकों से कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भीषण महंगाई में वर्तमान में महज क्रमशः 7000 रु० तथा 4000 रु० मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेविका का मानदेय 15 हजार और सहायिका का मानदेय 10 हजार रु० प्रति माह करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*125 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर, थाना-चकमेहसी के पंचायत मालीनगर स्थित कब्रिस्तान का खेसरा सं०- 3361 एवं उसकी परिधि 1317 फीट है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी 20 साल पूर्व अमानक तरीके से की गयी थी जिसके कारण चारो तरफ की दीवार जीर्ण-शीर्ण होकर गिर गयी है तथा माल-मवेशी एवं अन्य जानवर धड़ल्ले से उसमें प्रवेश कर कब्र की पवित्रता को भंग कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित कब्रिस्तान की जीर्ण-शीर्ण एवं टूटी हुई दीवार का नये सिरे से जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पार्कों का रख रखाव

*126 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्राधीन दो- तीन मुख्य पार्क हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पार्कों के रख – रखाव का जिम्मा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कटिहार के अधिकार क्षेत्र में है, परन्तु रख –रखाव नहीं हो पा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पार्कों की जर्जर स्थिति को देखते हुए रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम कटिहार को हस्तान्तरित एवं अधिकृत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वायु प्रदूषण कम कब तक

*127 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के विभिन्न शहर वायु प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में बने रहते हैं, हाल के दिनों में बेगूसराय शहर वायु प्रदूषण के लिए दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन के लिए सुर्खियों में रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता / संयोजन मे वायु की गुणवत्ता को मॉनिटर करने की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेगूसराय में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई उपाय करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विधि-सम्मत कार्रवाई कब तक

*128 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार, वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय में पदाधिकारियों की पदस्थापन अवधि विभागीय नियमानुसार 02 वर्ष निर्धारित है परंतु कुछ पदाधिकारी लगातार 10 वर्षों से मुख्यालय स्थापना में पदस्थापित हैं एवं उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जो कि कदाचार एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने की श्रेणी में आता है ;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के ज्ञापांक 5543308 दिनांक 19.12.2023 द्वारा कदाचार में संलिप्त ऐसे ही विशेष आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग के विरुद्ध छानबीन कराकर कार्रवाई करने संबंधित आदेश निर्गत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कदाचार में संलिप्त खण्ड 'ख' में वर्णित विशेष सचिव, वाणिज्य कर विभाग के विरुद्ध मुख्यालय पदस्थापन अवधि में लगे आरोपों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग से कराकर अविलंब

विधिसम्मत कार्रवाई करना चाहती है, ताकि सुशासन में कदाचार रुक सके, यदि हां तो कब तक ?

पटना.
25 जुलाई, 2024.

अखिलेश कुमार झा ,
सचिव, बिहार विधान परिषद्